

संक्षिप्त

नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार

सड़क अर्जुनी : तहसील के भुसारीटोला क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर डुग्गीपार पुलिस ने 55 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है.

पूर्व अपर मुख्य सचिव तागड़े करेंगे मार्गदर्शन

तिरोड़ा : जनगणना-2027 में बौद्ध धर्म व अनुसूचित जाति का सटीक पंजीयन, संवैधानिक आरक्षण के महत्व तथा डा. बाबासाहब आंबेडकर के आंदोलन के संदर्भ में जनजागरण करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी अभियान 1 सितंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक राज्य के प्रत्येक जिले व तहसील मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा. (सेवानिवृत्त छै) के नेतृत्व में अभियान का आयोजन किया जा रहा है.

जर्जर पुलों की मरम्मत पर मिल रहा आश्वासन

गोरेगांव : तहसील में इन दिनों जर्जर सड़कें चर्चा का विषय बने हुए हैं. वही इन्हीं सड़कों पर स्थित पुलों की स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं है. जो अब बारिश के दिनों में कभी भी किसी अप्रिय घटना का कारण बन सकते हैं. जिसमें पांगोली नदी पर स्थित म्हसगांव पुल, डक्का डिमरटोली सड़क पर स्थित पुल, कालीमाटी आसोली मार्ग पर स्थित पुल का समावेश है. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों पर स्थित अनेक सीढ़ी वर्क कार्य भी जर्जर अवस्था में है. जो दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं. इस विषय पर किसी जनप्रतिनिधि या किसी संबंधित अधिकारियों का भी ध्यान इस समस्या पर नहीं है.

रात में भी खेतों की रखवाली कर रहे किसान

देवरी : इन दिनों वन्यजीवों ने परेशानी बढ़ा रखी है. अब किसानों की मेहनत पर पानी फेरने का काम वन्यजीवों द्वारा किया जा रहा है. वन्यजीवों के झुंड क्षेत्र के वन इलाकों से सटे ग्रामों में आतंक मचा रहे हैं. जिससे किसान परेशान हैं. जंगली सुअरों के समूह खेतों में पहुंचकर फसलों को बर्बाद करने के साथ जमीन को खोद रहे हैं. ऐसे में मजबूरन किसानों को फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए खेतों में जागकर रखवाली करनी पड़ रही है.

पेड़ चुराने वाले पर मामला दर्ज

गोंदिया: अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत ग्राम घुसोबाटोला खेत परिसर से घुसोबाटोला निवासी आरोपी विजय डोमाजी मेंढे (45) ने सागौन के 15, बेर के 11, नीम के 4 व रोहन के 2 ऐसे कुल 32 पेड़ काटकर चुरा लिया. जिनकी कीमत 98 हजार रु. बताई गई है. भंडारा जिले के सानगडी निवासी फियादी किशोर उद्धव नंदनवार (50) की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

4.12 लाख रु. आभूषण चोरी

गोंदिया : ग्रामीण थाने के तहत झुलेलाल कॉलोनी, फुलचूर निवासी फियादी सुरेशकुमार हसानंद प्रिथ्वानी (61) यह परिवार के साथ मुवी देखने के लिए गए थे. इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में प्रवेश कर बेडरूम के अलमारी से 4 लाख 12 हजार 472 रु. कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिया. फियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच पुलिस उपनिरीक्षक सोनवाने कर रहे हैं.

देवरी-आमगांव मुख्य मार्ग पर भागी शिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना

नवनिर्माण इमारत का स्लैब गिरा; एक की मौत, तीन गंभीर

घायलों को गोंदिया ले जाया गया

देवरी तालुका के देवरी-आमगांव मुख्य मार्ग से सटे ग्राम भागी शिवार में निर्माणाधीन इमारत के निर्माण का स्लैब अचानक गिरने से बड़ी दुर्घटना हो गई। सोमवार (दि. 31 अगस्त) शाम करीब 4 बजे हुई इस घटना में एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, भागी शिवार में एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक स्लैब का कुछ हिस्सा गिर गया। इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर उसके नीचे फंस गए। अचानक हुई इस दुर्घटना से घटनास्थल पर

अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में दिनेश मदन नाईक (उम्र 38, निवासी मुल्ला) गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल 108 एंबुलेंस के माध्यम से देवरी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं रुपेंद्र राऊत (उम्र 35, निवासी कटंगी), भुमेंद्र घासले (उम्र 30, निवासी मुल्ला) और हितेंद्र खोब्रागडे (निवासी भंडंगा) ये तीन मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका देवरी ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए गोंदिया ले जाया गया है।



घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित तंत्र व स्थानीय नागरिकों ने घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई। घायल मजदूरों को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना से क्षेत्र में शोक व्यक्त किया जा रहा है, और निर्माण

स्थल पर सुरक्षा उपायों का अभाव था क्या, साथ ही स्लैब गिरने के पीछे आखिर सही कारण क्या है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।

इस बीच, इस घटना की आधिकारिक जांच कर निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा नियमों का पालन तथा संबंधित जिम्मेदार

व्यक्तियों की भूमिका की जांच होना जरूरी है, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। एक मजदूर की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और गंभीर रूप से घायल तीनों मजदूरों की हालत को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

खड़े वाहन दे रहे हादसों को न्योता

संवाददाता / सड़क अर्जुनी कोलकाता-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग पर कोहमारा के नवेगांवबांध टी-पॉइंट तथा गोंदिया की ओर जाने वाले टी-पॉइंट के पास सड़क किनारे भारी वाहन खुलेआम खड़े किए जा रहे हैं. मोड़ के समीप खड़े इन वाहनों के कारण आने-जाने वाले वाहन चालकों के लिए गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. नागरिकों ने सवाल उठाया है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना और जनहानि के बाद ही प्रशासन जागेगा. राष्ट्रीय महामार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार के बीच टी-पॉइंट के मोड़ पर भारी वाहनों के खड़े रहने से सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते. अचानक सामने वाहन आने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है. रात के समय यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. इसके बावजूद संबंधित स्थानों पर बड़ी संख्या में भारी वाहन खड़े किए जा रहे हैं. महामार्ग के किनारे वाहन खड़े करने को लेकर यातायात नियम लागू हैं. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी किए जाने से वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है.



नागरिकों का कहना है कि दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन को पहले ही प्रतिबंधात्मक कदम उठाने चाहिए. राष्ट्रीय महामार्ग पर यातायात को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी महामार्ग पुलिस के साथ स्थानीय पुलिस विभाग की भी है. ऐसे में खतरनाक मोड़ पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ नियमित गश्त, दंडात्मक कार्रवाई और आवश्यक स्थानों पर प्रभावी नो-पार्किंग व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है. नागरिकों का कहना है कि संबंधित विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करें और सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें.

जानवा-येगांव मार्ग की बदहाली से परिसर के नागरिक परेशान

संवाददाता / अर्जुनी मोर तहसील के येगांव से जानवा तक जाने वाले प्रमुख मार्ग की हालत इन दिनों अत्यंत खराब हो गई है. सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने से स्कूली विद्यार्थियों, किसानों, दोपहिया वाहन चालकों तथा आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अर्जुनी मोरगांव तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक इस सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति के कारण यात्रा करना जोखिमपूर्ण और कठिन हो गया है. बारिश के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का



अंदाजा नहीं लग पाता. इससे विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है. वहीं कृषि उपज की दुलाई करने वाले किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने संबंधित निर्माण

विभाग से सड़क का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है. जानवा ग्राम पंचायत के प्रशासक तथा कृषि उपज बाजार समिति अर्जुनी मोरगांव के संचालक किशोर ब्राह्मणकर, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों व ग्रामवासियों ने मांग की है कि संबंधित विभाग, जिप सदस्यों तथा शासन इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देकर जानवा-येगांव मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराए अथवा नए सड़क निर्माण की मंजूरी दी जाए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो नागरिकों की दैनिक आवाजाही की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है.

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए : विधायक बडोले

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना की कछुआ गति पर जतायी नाराजगी

संवाददाता / सड़क अर्जुनी किसानों के हित में सरकार हर वर्ष विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं लागू की जाती हैं। कृषि विभाग अंतर्गत डेढ़ वर्ष से नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन योजना की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो रही है। अर्जुनी मोरगांव विस क्षेत्र के करीब 1700 किसानों ने योजना के विभिन्न घटकों का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक केवल 23 किसानों को ही लाभ मिल पाया है। इस पर विधायक राजकुमार बडोले ने योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी



जताई। वे सड़क अर्जुनी तहसील कार्यालय के सभागार में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्रता रखने वाले अंतिम किसान तक पहुंचना चाहिए।

योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1700 ने किया आवेदन, लाभ केवल 23 किसानों को नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना

के तहत अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र के करीब 1700 किसानों ने खेत तालाब, बांस रोपण, बकरी पालन, फल बागान, सूक्ष्म सिंचाई, वॉटर पंप, ड्रिप सिंचाई, गोद फार्म, शहतूत की खेती और तुषार सिंचाई सहित विभिन्न घटकों का लाभ लेने आवेदन किए हैं। कृषि अधिकारियों के अनुसार, इनमें से केवल 23 किसानों को ही योजना का लाभ मिल सका है। इससे योजना के क्रियान्वयन की धीमी गति का अंदाजा लगाया जा सकता है। समीक्षा बैठक में योजना के लंबित आवेदनों का निपटारा कर पात्र किसानों तक जल्द से जल्द लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

जन्माष्टमीच्या पावन पर्वा निमित्त गोंदिया शहरात प्रथमच 'दिव्य वृंदावन महोत्सव'चे आयोजन करण्यात आले आहे. बालकृष्ण उत्सव मंडळ व श्रीराम रामायण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बजरंग नगर, राजगोपाल वॉर्ड येथे 4 ते 6 सप्टेंबर 2026 दरम्यान विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.

महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी, 4 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता युगल सरकार श्यामा-श्याम यांचे नगरभ्रमण काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी 3 वाजता विशेष पूजन व अभिषेक होईल. सायंकाळी 7 वाजल्यापासून सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहिका सोनालीजी नागेश्वर यांच्या मधुर वाणीतून भजनसंस्था आयोजित करण्यात आली आहे. 5 सप्टेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता भोले के दिवाने

गुप, आमगाव यांच्या वतीने 12 ज्योतिर्लिंग संगीतमय शिवरुद्राभिषेक आयोजित करण्यात आला आहे. या पावन अभिषेकात पूजन करू इच्छिणाऱ्या भाविक जोडव्यानी समितीच्या 9309528214 व 9637438183 या मोबाईल क्रमांकांवर संपर्क साधून आपली जागा निश्चित करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महोत्सवाच्या अंतिम दिवशी, 6 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता गोपाळकाला, तर सायंकाळी 4 वाजल्यापासून भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. आयोजन समितीने सर्व भाविकांना कुटुंबासह महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ प्रेक्षक न बनता या दिव्य वृंदावन महोत्सवाचा अविभाज्य भाग व्हावे आणि आपल्या गोंदिया शहरातच वृंदावनच्या अलौकिक अनुभूतीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन समितीने केले आहे.

गुप, आमगाव यांच्या वतीने 12 ज्योतिर्लिंग संगीतमय शिवरुद्राभिषेक आयोजित करण्यात आला आहे. या पावन अभिषेकात पूजन करू इच्छिणाऱ्या भाविक जोडव्यानी समितीच्या 9309528214 व 9637438183 या मोबाईल क्रमांकांवर संपर्क साधून आपली जागा निश्चित करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महोत्सवाच्या अंतिम दिवशी, 6 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता गोपाळकाला, तर सायंकाळी 4 वाजल्यापासून भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. आयोजन समितीने सर्व भाविकांना कुटुंबासह महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ प्रेक्षक न बनता या दिव्य वृंदावन महोत्सवाचा अविभाज्य भाग व्हावे आणि आपल्या गोंदिया शहरातच वृंदावनच्या अलौकिक अनुभूतीचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन समितीने केले आहे.

घर की जगह अस्पताल में प्रसूति पर जोर, मातृ वंदना योजना बनी वरदान



4 साल में 74,000 से अधिक प्रसूतियां अस्तालों में

संवाददाता / गोंदिया सुरक्षित मातृत्व व नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से संस्थागत प्रसूति को बढ़ावा दिया जा रहा है. घर पर प्रसूति के बजाय सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रसूति कराने के लिए महिलाओं

को प्रोत्साहित किया जा रहा है. जिले में पिछले चार वर्षों के दौरान 74 हजार 404 महिलाओं की प्रसूति अस्पतालों में कराई गई. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, संस्थागत प्रसूति को बढ़ावा मिलने से घर पर प्रसूति कराने की घटनाओं में कमी आई है. जन्म के बाद नवजात को बीसीजी,

पोलियो व हेपेटाइटिस-बी का पहला टीका भी दिया जाता है. माताओं को स्तनपान, नवजात शिशु की देखभाल व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है. संस्थागत प्रसूति को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न

आर्थिक व स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही हैं. सरकारी अस्पतालों में प्रसूति कराने वाली गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है. गर्भवती महिलाओं व बीमार नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क प्रसूति, सिजेरियन, दवाएं तथा 102/108 एंबुलेंस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा

उपलब्ध कराई जाती है. पहले व दूसरे अपत्य के समय, विशेषकर दूसरी संतान के रूप में बेटी होने पर, गर्भवती व स्तनदा माताओं को पोषण आहार व विश्राम के लिए चरणबद्ध आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाती है.



संपादकीय

‘प्रलय’ के 1 8 9 ग्लेशियर

भारत भी प्रलय और तबाही के कगार पर है। नेपाल में भी महाविनाश अब भी दस्तक दे रहा है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने अध्ययन किए हैं और उनकी रपटों के निष्कर्ष हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में करीब 7500 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। उनमें से 189 झीलें ‘रेड जोन’ में हैं, क्योंकि ये कभी भी टूट-फूट कर ‘प्रलय’ मचा सकती हैं। तब तबाही निश्चित है। एक रपट यह भी है कि 491 सालों में 254 बार ग्लेशियर झीलें फट चुकी हैं। फिलहाल उत्तराखंड में ‘हैमिंग ग्लेशियर’ सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अध्ययन में यह सामने आया है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर हजारों छोटी-बड़ी झीलें हैं। सिर्फ लद्दाख क्षेत्र में ही 3219 ग्लेशियर झीलों की पहचान की जा चुकी है। कुल 2431 ग्लेशियर झीलें 10 हेक्टेयर से भी बड़ी हैं। घोर चिंता यह है कि एनडीएमए ने इन 189 झीलों को ‘अत्यधिक जोखिम’ की श्रेणी में रखा है। सवाल यह है कि क्या हमारे भू-वैज्ञानिक, विशेषज्ञ इन झीलों के ‘प्रलय’ से देश के संभावित हिस्सों को बचाने में सफल नहीं हो सकते? क्या अब पर्यावरण, जलवायु-परिवर्तन और वैश्विक गर्मी के असंतुलन बढ़ा लेने की स्थिति में आ गए हैं? नेपाल के संदर्भ में भी चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी की है कि आगामी 3 डिन (शुक्रवार समेत) खतरे से भरे हैं। ग्लेशियर झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ, तो झील में दरार पड़ें? का खतरा है, नतीजतन वह ‘प्रलयी सैलाब’ में तबदील हो सकता है। यानी नेपाल में खतरे और विनाश की घंटियां अब भी बज रही हैं। नेपाल छोटा-सा देश है, जिसकी कुल अर्थव्यवस्था 4.48 लाख करोड़ रुपए है। मौजूदा जल-प्रलय ने नेपाल की करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां तबाह कर दी हैं। सरकार ने फिलहाल यह आकलन किया है। शुक्रवार सुबह तक 469 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है, क्योंकि इतने शव बरामद कर लिए गए हैं। मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश-विदेश के करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, 288 भारतीयों के सुदाम अभी तक नहीं मिले हैं। इस त्रासद घड़ी में विश्व बैंक ने 25 अरब रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। कुछ और देशों ने भी आर्थिक ऐलान किए हैं। भारत की सेना, एनडीआरएफ, एएसबी आदि के जवान और डॉक्टर-नर्सिंग स्टाफ नेपाल को संकट से उबारने में संलग्न हैं। भारत लगातार राहत-सामग्रियों की भी आपूर्ति कर रहा है। बहरहाल हमारे सामने ग्लेशियर झीलों के अलावा, अल-नीनो, ग्लेशियर के निरंतर पिघलने, शहरी प्रदूषण और बीमारियां, कृषि-संकट आदि भी आसन्न तबाही और त्रासदियों की दस्तक दे रहे हैं। भारत कई जल-प्रलय झेल चुका है। जून, 2013 में केदारनाथ के ‘प्रलय’ और अलकनंदा-मंदाकिनी नदियों की बाढ़ में हजारों मौतें हो गई थीं। उसे ‘सबसे बड़ी त्रासदी’ करार दिया गया था। चमोली-ऋषि गंगा घाटी में ग्लेशियर फूटा था, जिसमें 200 मौतें हुई थीं। केरल में वायनाड में भूस्खलन और मसालाथार बारिश में न केवल 400 के करीब मौतें हुईं, बल्कि कई गांव भी तबाह हो गए। नामोनिशान भी नहीं बचा। भारत में चक्रवात, भूकंप, सैलाब आते रहे हैं, बाढ भी फटते हैं, बिजली भी गिरती है, नतीजतन असंख्य मौतें होती रही हैं। हालांकि अब समय-पूर्व कुछ जानकारीयां दी जाती हैं, उतारखंड में ही चिह्नित 426 बड़ी ग्लेशियर झीलों में से 25 को ‘संवेदनशील’ और 13 झीलों को ‘अति संवेदनशील’ आंका है। इनमें भिलंगा घाटी में मौजूद ‘मसर ताल’ बेहद संवेदनशील बताई गई है। विनाश और त्रासदियों के लिए एक ही झीर पर्याप्त है, लिहाजा हमें अभी से सतर्क होना चाहिए कि नदियों के किनारे निर्माण नहीं हों। मंदिर भी नदी किनारे न हो और सरकार को बाध्य किया जाए कि नदियों को आपस में जोड़े का काम अब युद्धस्तर पर किया जाए।

विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन

नागपुर: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने सोमवार को नैनजमेंट काउंसिल की बैठक के दौरान कुलपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. संगठन ने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताओं और जांच के बावजूद दोषी कंपनियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 100 और 500 रुपए के नोटों पर कथित भ्रष्टाचार से जुड़े नाम और अपनी मांगें लिखकर तोरण की तरह टांग दिया, साथ ही लिखित शिकायतें शिकायत पेटी में डाल दीं. संगठन का आरोप है कि विवि में चल रही जांच प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांचकर्ता और आरोपी



एक ही पक्ष प्रतीत होते हैं. एनएसयूआई ने कुलपति की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है.

प्रदर्शन के दौरान पांच प्रमुख मुद्दे उठाए गए. इसमें सफाई कर्मचारियों के वेतन में कथित घोटाला, टेंडर खर्च को लाखों से

करोड़ों तक बढ़ाना, शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, विवि गीत के गिनीज रिकॉर्ड कार्यक्रम पर पांच लाख की जगह 95 लाख रुपए खर्च करने का आरोप और कोएफएफ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर शर्तों में हेरफेर शामिल हैं. एनएसयूआई ने मांग की कि जांच समितियां जल्द फैसला लें, श्रीनिवास और केएचएफएम/केएचएम जैसी दोषी ठेका कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोषियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो. प्रदर्शन में अजित सिंह, वैष्णवी भारद्वाज, आशीष मंडपे, प्रणय ठाकुर, नीलेश खोगड़े, मुरली साहू, नागेश गिन्है, विद्यासागर त्रिपाठी, आयुष गोरले, प्रणय कुंभलकर, दयाशंकर साहू और रॉयल

कुलपति कार्यालय के बाहर भ्रष्टाचार के खिलाफ टांगा १००-५०० के नोटों का तोरण

गेडाम आदि पदाधिकारी उपस्थित थे. **आरोपों के बाद जांच ने पकड़ी रफ्तार** एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारियों के वेतन से कथित अवैध वसूली का मुद्दा उठाने के बाद अब विश्वविद्यालय ने जांच समिति गठित की है. समिति के निर्देश पर एनएसयूआई के अजित सिंह को संबंधित चार कर्मचारियों के साथ 1 सितंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि कर्मचारियों को लेकर मामला केएचएफएम हॉस्पिटैलिटी एंड फैंसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज तथा श्रीनिवास हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज से जुड़ा है. इससे एनएसयूआई के उठाए मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने का संकेत मिलता है.

यूपी से बेटी से मिलने आए पिता को दोपहिया ने उड़ाया

नागपुर : सीताबर्डी थाना क्षेत्र के धरमपेट इलाके में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार दोपहिया चालक ने पैदल जा रहे ४६ वर्षीय अंधेड़ व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी फरार हो गया. घायल शख्स मूलतः लॉट क्र. २१९९, विवेक नगर, सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी रितेश त्रिभुवनदास अग्रवाल (४६) है और वे नागपुर में पढ़ रही अपनी बेटी से मिलने आए थे. उनका निजी अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज जारी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रितेश अग्रवाल की १६ वर्षीय बेटी उमति नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है. वे अपनी बेटी से मिलने के लिए सुलतानपुर से नागपुर आए हुए थे और धरमपेट स्थित 'धरमपेट हाउस होटल' में ठहरे थे. शनिवार, २९ अगस्त की शाम करीब

५-४५ बजे वे धरमपेट में बटुकभाई ज्वेलर्स के पास स्थित राजभंडार मिष्ठान भंडार से मिठाई खरीदकर पैदल ही होटल की ओर लौट रहे थे. तभी टीवीएस जुपिटर क्र. एमएच ४९ सीबाय १९८२ के चालक ने अपने दोपहिया वाहन को अत्यधिक तेज गति, लापरवाही और खतरनाक तरीके से चलाते हुए सड़क किनारे चल रहे रितेश अग्रवाल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रितेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने लहलुहान रितेश अग्रवाल को तुरंत जगनाई चौक स्थित सेवन स्टार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में उपचार जारी है.

अधिकारियों को धमकाने का सिलसिला जारी

संवाददाता । नागपुर महिला सशक्तिकरण के नाम पर सत्तापक्ष नेता का पद छोड़कर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष और सभी विषय समितियों के सभापति पदों की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है. इतना ही नहीं, जोन सभापतियों का पद भी महिलाओं के हाथों में देकर भाजपा की ओर से मनपा में महिला राज होने का दावा किया जा रहा है. लेकिन वास्तविकता यह है कि महिला पार्षदों के पतियों का मनपा के कामकाज में हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है. जोन सहायक आयुक्तों व अधिकारियों की

तरफ से कामकाज की दृष्टि से तैयार किए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भी महिला पार्षदों के पतियों को जोड़ दिया गया है. कुछ पार्षदों के रिश्तेदार और बच्चे भी ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं. ऐसे में अधिकारी परेशान हो रहे हैं. खास बात यह है कि ये रिश्तेदार अब सीधे जोन के अधिकारियों को धमकाने, गाली-गलौज करने और अपमानित करने जैसी हरकतें कर रहे हैं.

ज्ञात हो कि पिछली आम सभा के अंत में महापौर नीता ठाकरे ने सदन में जाहिर तौर पर कहा था कि महिला पार्षदों के पतियों व रिश्तेदारों द्वारा अधिकारियों को



धमकाने के मामले सामने आए हैं. ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना चाहिए. लेकिन अभी भी यह काम चल रहा है.

शासन के निर्णय के अनुसार पार्षदों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं

रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा

इस्पात कंपनी की समस्याएं जानी

संवाददाता । वर्धा

उद्योग मंत्री उदय सामंत ने देवली स्थित एसएमडब्ल्यू इस्पात प्लांट का दौरा किया. इस समय उन्होंने इस्पात प्लांट की उत्पादन प्रक्रिया तथा वहां उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीक का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित रहे. दौरे के दौरान उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कंपनी के प्रबंधन एवं कर्मचारियों से संवाद किया तथा प्लांट के कामकाज और उत्पादन गतिविधियों की जानकारी ली.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर अग्रणी बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. विदर्भ जैसे क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे क्षेत्रीय संतुलित विकास को भी बढ़ावा मिलता है. मंत्री उदय सामंत ने एसएमडब्ल्यू इस्पात जैसे उद्योगों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे उद्योग ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए



रोजगार और विकास के नए द्वार खोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि उद्योग हितैषी नीतियों के कारण महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है. साथ ही उद्योगों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं एवं अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है.

इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कंपनी के प्रबंधन के साथ उद्योग के विस्तार, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा भविष्य की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने राज्य के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उद्योगों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. इस सफल दौरे एवं सकारात्मक चर्चा के संबंध में कंपनी के निदेशक दीपक सुमद ने कहा कि उद्योग मंत्री के साथ हुई

यह चर्चा अत्यंत फलदायी एवं मार्गदर्शक रही. इससे पूरे उद्योग जगत में एक नया उत्साह पैदा हुआ है.

सरकार के ऐसे मजबूत सहयोग एवं समर्थन से हमें अपने प्रोजेक्ट के विस्तार तथा उत्पादन क्षमता को और अधिक गति से बढ़ाने की बड़ी प्रेरणा मिली है. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार और उद्योग जगत के बीच निरंतर संवाद एवं सहयोग से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सकती है. एसएमडब्ल्यू कंपनी भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. उद्योग मंत्री के इस उच्चस्तरीय दौरे को औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

दबाव के कारण कानूनी कार्रवाई नहीं

यदि महिला पार्षदों के पति या रिश्तेदार बिना अधिकार प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और अधिकारियों को गाली देते या धमकाते हैं, तो सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है.

हस्तक्षेप पर रोक सिर्फ कागजों पर

पार्षदों के रिश्तेदारों का कार्यालयों में चक्कर लगाना, फाइलें लेकर घूमना और अधिकारियों को धमकाना कानूनी रूप से प्रशासनिक कार्यों में अवैध हस्तक्षेप माना जाता है. हालांकि, ऐसा लगता है कि यह रोक फिलहाल केवल कागजों तक ही सीमित है. १५१ सदस्यों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक होने के बावजूद सत्ता की बागडोर पतिराज व रिमोट कंट्रोल संस्कृति के हाथों में जाने की तस्वीर दिखाई दे रही.

है. इसके बावजूद कुछ पार्षदों के पति और रिश्तेदार सीधे विकास कार्यों की फाइलें

लेकर जोन कार्यालय और मनपा मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं.

महामाया के जाल में एमपीसीबी मुख्यालय !

पर्यावरण को नुकसान पहुंचने पर भी नहीं लगाया दंड

संवाददाता । चंद्रपुर चंद्रपुर तहसील के बेलसनी स्थित महामाया इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 'माया' में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल इस कदर उलझ गया है कि उसे न तो उगलते बन रहा है और न ही निगलते हुए. महामाया इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उठाए गए कदम से चंद्रपुर स्थित प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय से लेकर मुंबई मुख्यालय तक, विभाग के एसओपी का उल्लंघन करता हुआ साफ नजर आ रहा है.

एमपीसीबी चंद्रपुर स्थित विभाग के प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव ने लिखित आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि वह मुख्यालय के आदेश पर 'ओपनिंग' आदेश दे रहे हैं जिससे



एमपीसीबी मुख्यालय स्वयं संदेह के घेरे में आ गया है. जिससे सवाल उठता है कि जिस विभाग पर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी है वह विभाग स्वयं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संवेदनशील नहीं है.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के

अध्यक्ष विभाग के सिद्धेश कदम तथा विभाग के सदस्य सचिव आईएस अधिकारी राहुल रेखावार हैं. पर्यावरण विभाग को पंकजा मुंडे संभाल रही हैं. वह स्वयं यहां का दौरा कर प्रदूषण को लेकर चिंता जता चुकी है. इसके बावजूद विभाग की असंवेदनशीलता का

सिरोंचा को अब भी बस डिपो का इंतजार

सिरोंचा : ऐतिहासिक

विरासत वाले और गढ़चिरोली जिले के पुराने तहसील मुख्यालयों में शामिल सिरोंचा शहर को अब तक पूर्ण क्षमता वाला एसटी बस डिपो नहीं मिल पाया है. पिछले कई वर्षों से नागरिकों द्वारा बस डिपो की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह मुद्दा लंबित है. इसके कारण यात्रा, शिक्षा, शासकीय कार्यों के साथ सामाजिक

एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सिरोंचा तहसील में 148 गांव हैं. तहसील मुख्यालय होने के कारण विभिन्न सरकारी कार्यालयों, बैंकों और बाजारों के लिए रोजाना बड़ी संख्या में

नागरिक सिरोंचा आते-जाते हैं. वर्तमान में जिले में गढ़चिरोली और अहरी में एसटी डिपो हैं. अहरी सिरोंचा से करीब 110 कि. मी. और गढ़चिरोली करीब 220 कि. मी. दूर है. ऐसे में सिरोंचा के लिए

नियमित बस उपलब्ध कराने में परेशानी होती है.

दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई विद्यार्थी शिक्षा के लिए सिरोंचा आते हैं. पर्याप्त बसें नहीं होने से उन्हें स्कूल-कॉलेज आने-जाने में परेशानी होती है. विवाह, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराना भी मुश्किल रहता है. सिरोंचा क्षेत्र में त्रिवेणी संगम, वडथम का ज्युरसिक पार्क, कालेश्वरम देवस्थान और मेडिगाड्डा बैराज जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हैं. पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं होने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है.

वर्धा में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ दर्ज किए १२८ मामले

वर्धा : जिले में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण की श्रृंखला पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए वर्धा पुलिस ने 29 से 30 अगस्त 2026 तक बेहद सुनियोजित तरीके से 'वॉशआउट' अभियान चलाया. इस कार्रवाई के दौरान जिले में 25 अवैध देसी, विदेशी शराब बिक्री के मामले तथा 103 देसी शराब बिक्री के मामले, इस प्रकार 128 मामले दर्ज किए गए. इस कार्रवाई में करीब 1 करोड़ 4 लाख 95 हजार 75 रुपए का शराब स्टॉक और संबंधित सामग्री जब्त करके नष्ट की गई.

एसपी सौरभ कुमार अग्रवाल ने पूरे मामले की समीक्षा कर इस 'सर्जिकल स्ट्राइक' की योजना तैयार की. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में अवैध शराब विक्रेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर



शराब तैयार कर उसका भंडारण किया जा रहा है.

इस सूचना के आधार पर अवैध शराब भट्टियों वाले स्थानों, विशेषकर शहर से सटे इलाकों, गांवों के बाहर, जंगल और ऐसे दुर्गम स्थानों पर गोपनीय निगरानी रखी गई. जहां आसानी से पहुंचना मुश्किल है. इसके साथ ही बाहरी जिलों से चोरी-छिपे बिक्री के लिए लाई जाने वाली देसी-विदेशी

शराब के विक्रेताओं और बिक्री के स्थानों पर भी नजर रखी गई.

पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल के नेतृत्व और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन में जिले के 4 एसडीपीओ, 37 अधिकारी, अपराध शाखा सहित 263 पुलिसकर्मियों ने अभियान में हिस्सा लिया. 29 अगस्त की सुबह 6 बजे से सभी अवैध शराब भट्टियों और देसी-विदेशी शराब बिक्री के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. कार्रवाई में 129 आरोपियों के खिलाफ 128 मामले दर्ज किए गए. एसपी सौरभ कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वर्धा जिले में अवैध शराब का किसी भी प्रकार का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नई सोलर नीति से आर्थिक संकट में उद्योग

इंडस्ट्रियलिस्ट एसो. ने उद्योगमंत्री सामंत समक्ष रखी समस्याएं



संवाददाता । वर्धा नए सोलर नीति के कारण उद्योग आर्थिक संकट में होने की बात वर्धा जिला इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने उद्योग मंत्री डा. उदय सामंत, पालकमंत्री डा. पंकज भोयर के समक्ष रखी. उद्योजकों की समस्याओं को जाना तथा जिसका निराकरण करने के संदर्भ में उपाययोजना करने का उद्योगमंत्री ने आश्वासन दिया है. बैठक में वर्धा जिला एमआईडीसी

इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण हिवरे ने बताया कि, मार्च 2026 निर्माी करने के लिए सोलर फ़ैट लगाकर बिजली निर्मिती कर उपयोग में ला रहे थे. इसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर लाखों रुपए खर्च किए, जिसमें उनके सोलर प्लैंट द्वारा निर्मित होनेवाली बिजली उद्योजक लिए उद्योजक व एमआसईडीसीएल विद्युत विभाग ने समझौता भी किया था. लेकिन

बापू कुटी के कारण कई उद्योगों पर पाबंदी

बापू कुटी होने से वर्धा एमआईडीसी में कई उद्योग स्थापन करने को फरवरी 1994 के केंद्र सरकार के आदेशनुसार बंदी है. जिससे जिन उद्योगों से प्रदूषण होता नहीं, ऐसे उद्योगों को अनुमती मिलने के लिए केंद्र सरकार की ओर प्रस्ताव भेजर मंजूरी दी जाए. उद्योग को मिलने वाले अनुदान, नियमित दे आदि मांग के संदर्भमें चर्चा संगठन के मार्फत बैठक में उद्योगमंत्री व पालकमंत्री के साथ चर्चा हुई. इस समय उद्योजकों ने रखी समस्याओं का जल्द कैंसे निराकरण करना संभव हो, इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेकर तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया, उद्योगमंत्री उदय सामंत ने तीन दिन में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को दिए.

महाराष्ट्र सरकार विद्युत विभाग के नई नीति के अनुसार मार्च 2026 से उद्योजक अपने सोलर प्लैंट से प्रतिदिन 500 युनिट बिजली निर्माण करता है व उद्योजक सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 300 युनिट उपयोग करता है, तो 200 युनिट एमएसईडीसीएल विद्युत विभाग को निःशुल्क देना पड़ेगा. इस बचे हुए युनिट का फायदा रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं ले सकते हैं. जिससे सोलर पर बिजली निर्माण करने के बावजूद जिसपर पाबंदी लगाई है. निर्माण

होने वाली सोलर बिजली पर 1.80 पैसे ग्रिड चार्ज लगाया जाता है. जिससे उद्योजकों पर बड़ा आर्थिक कसकट निर्माण हो गया है.

अन्य राज्य की तुलना में महाराष्ट्र में बिजली के रेट जादा है. इसके पहले सरकारी खरीदी में करीब 40 प्रश वस्तु स्थानीय उद्योजकों ने निर्माण किए आईएसआई निकष के अनुसार खरीदी करना बंधनकारक था. जिससे स्थानीय उद्योजकों को अपना उत्पादीत किया व

सरकार को चाहिए वह वस्तु बेचना संभव था. लेकिन अब किसी भी सरकारी कार्यालय में नियम का पालन नहीं हो रहा है. सभी कार्य प्लंबिंग एक्त्रित कर जाचक शर्त डालकर स्थानीय उद्योजकों से कोई भी वस्तु खरीदी करते नहीं, जिसपर प्रभावी रूप से अंमल करने के लिए उद्योग विभाग ने कार्यवाही करना जरूरी है. उद्योजकों को कारखाना परिसर में पानी उपयोग के लिए विधन कुआ खोदने के लिए उद्योजकों को नो ऑब्जेक्शन अनेक मांगों का समावेश है.

इस समय पालकमंत्री डा. पंकज भोयर ने एमआईडीसी में उद्योगों को बढ़ावा देने जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए, बैठक में जिलाधिकारी वान्मथी सी. , उद्योग विभाग के सहआयुक्त शिवकुमार मुद्दमवार, सहा. आयुक्त सुनिल हजारे उपस्थित थे. उद्योजक दत्तात्रय जोशी, ब्रजेश पांडे, हरीष हांडे, मनोज पावडे, सचिन डांगे, गिरीष टिबडेवाल, आयुष सिंघानिया, अज्जू नंदकिशोर कुलधरीया, शांताराम अवचट, एड. अर्चना घोडे समेत जिले के अनेक उद्योजक सभा में शामिल हुए थे.

जिले में 10,877 ग्राहक शामिल, कम लागत में बिजली हो रही उपलब्ध



संवाददाता । वर्धा आम नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम लागत में स्वच्छ एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने वाली 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप' अर्थात 'स्मार्ट' योजना को नागपुर परिमंडल में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहकों ने महावितरण के पास आवेदन किए हैं. इनमें वर्धा जिले के 10 हजार 877 ग्राहक शामिल हैं. केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी के कारण यह योजना आम नागरिकों के लिए लाभदायक साबित हो रही है.

प्राप्त आवेदनों में से वर्धा जिले के 5 हजार 701 ग्राहकों के अंदाजपत्रक तैयार किए जा चुके हैं. इस योजना में पहले डिमांड शुल्क जमा करने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाएगी. योजना के लिए लाभार्थियों की निर्धारित संख्या तय की गई है. इसलिए 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर पात्र ग्राहकों को लाभ दिया जाएगा. निर्धारित संख्या

पूरी होने के बाद अंदाजपत्रक तैयार होने के बावजूद शुल्क जमा करना संभव नहीं होगा. इसे ध्यान में रखते हुए महावितरण ने अंदाजपत्रक प्राप्त सभी पात्र ग्राहकों से तत्काल शुल्क जमा करने की अपील की है. योजना के लिए सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच ग्राहक की औसत बिजली खपत 100 यूनिट तक होना अनिवार्य है.

केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से 80 से 95 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने के कारण पात्र लाभार्थी मात्र नाममात्र की राशि में 1 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे. इस योजना के तहत 30 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्राहकों के लिए केवल 2,500 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्राहकों के लिए 5,000 रुपये, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए 10,000 रुपये लाभार्थी महिस्सा निर्धारित किया गया है.

राष्ट्रीय खेल दिवस पर किया आयोजन, युवाओं में दिखा जोश

‘संडे ऑन साइकिल’ रैली को भारी प्रतिसाद

संवाददाता । गड़चिरोली राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला खेल कार्यालय एवं साइकिल स्नेही मंडल, गड़चिरोली के संयुक्त तत्वावधान में रविवार ‘संडे ऑन साइकिल’ रैली का आयोजन किया गया. रैली का मार्ग इंदिरा गांधी चौक से क्रीड़ा प्रबोधिनी, पोटेगांव रोड तक निर्धारित किया गया था. इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, नागरिकों एवं साइकिल प्रेमियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर रैली को उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया. नगराध्यक्ष एड. प्रणोती सागर निबोरकर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का शुभारंभ

किया. इस अवसर पर जिला क्रिडा अधिकारी भास्कर घाटोले, साइकिल स्नेही मंडल के जिला महासचिव उदय धकाते, राकां के जिलाध्यक्ष रवींद्र वासेकर, समाजसेवी उपेंद्र रोहनकर, प्रा. सुनीता सालवे, सुचिता धकाते समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे. इस दौरान नगराध्यक्ष एड. प्रणोती निंबोरकर ने रैली में शामिल विद्यार्थियों नागरिकों एवं साइकिल प्रेमियों का मार्गदर्शन करते हुए साइकिल चलाने के स्वास्थ्यवर्धक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि, नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और

तंदुरुस्त रहने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है. इसलिए दैनिक जीवन में अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करने का उन्होंने आहवान किया. इस अवसर पर साइकिल स्नेही मंडल के मुरलीधर दोनाडकर, विजय सालवे, वरुण धोड़रे, उल्हास आखाड़े, गिरीश कांबले, कुणाल पेंदोरकर, सुभाष धांदरे, गुरुदेव रोहनकर, शरद गिरीपुंजे समेत मंडल के सदस्य तथा जिला क्रिडा कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन ऋषिकांत पापड़कर ने किया.

10.470 किलो गांजा किया जब्त, 1 अरेस्ट



संवाददाता । वर्धा मध्य बल रेलवे के नागपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा (आरपीएफ) ने ऑपरेशन नाकोंस के तहत कार्रवाई करते हुए 10.470 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख 23 हजार 500 रुपये बताई गई है. ट्रॉली बैग सहित कुल जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 5.25 लाख रुपये है. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. मुंबई सीएसएमटी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मादक पदार्थों के परिवहन की सूचना पर सीआईबी/आरपीएफ नागपुर, सीपीडीएस नागपुर और ज्ञान पाठक नागपुर की संयुक्त टीम ने प्रशिक्षित खोजी कुत्ते प्रिस के साथ ट्रैन की जांच की. सिंदी रेलवे और वर्धा के बीच जांच के दौरान बी-2 कोच की बर्थ नंबर 11 पर एक संदिग्ध यात्री

मिला. पूछताछ में उसकी मनीषकुमार निवासी पटमनीष कसार के रूप में हुई. उसके ट्रॉली बैग की जांच में गांजा होने की जानकारी सामने आई. खोजी कुत्ते प्रिस ने भी मादक पदार्थ की मौजूदगी का संकेत दिया. वर्धा में ट्रैन का निर्धारित ठहराव नहीं होने के कारण अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गई.

राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में बैग की तलाशी लेने पर 10 पैकेट गांजा मिला, जिसका वजन 10.470 किलो था. गांजे की कीमत करीब 5,23,500 रुपये तथा ट्रॉली बैग की कीमत 1,500 रुपये आंकी गई. इसके अलावा दो मोबाइल फोन और यात्रा टिकट भी जब्त किए गए. गिरफ्तार व्यक्ति और जब्त सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी वर्धा को सौंप दिया गया.



संवाददाता । देसाईगंज आरमोरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों, मेहनतकशों, आदिवासियों, निराधार नागरिकों, बेरोजगारों तथा महंगाई और स्मार्ट मीटर से परेशान नागरिकों के न्यायसंगत अधिकारों के लिए कांग्रेस की ओर से 31 अगस्त को देसाईगंज के उपविभागीय कार्यालय पर महामोर्चा निकाला गया. आरमोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक

रामदास मसराम के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे में सैकड़ों किसान, खेतिहर मजदूर, मेहनतकश और बेरोजगार युवक शामिल हुए. ढोल-ताशों की गूंज के बीच बैलगाड़ियों के साथ निकले गए इस मोर्चे ने उपविभागीय कार्यालय पर दस्तक दी. इस दौरान देसाईगंज के उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान के माध्यम से सरकार को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन



एसडीएम कार्यालय पर महामोर्चा

बैलगाड़ियों के साथ दी दस्तक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीपीओ को सौंपा ज्ञापन

में आम जनता और गरीब वर्ग की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के मांग की गई. मोर्चे में देसाईगंज पंस के पूर्व सभापति परसराम टिकले, कांग्रेस के कुरखेड़ा तहसील अध्यक्ष जीवन पाटील नाट, देसाईगंज के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, आरमोरी के तहसील अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, कोरची के तहसील अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, पूर्व उपसभापति नितीन राऊत, श्रीराम दुग्गा, प्रशांत कोराम, वामनराव सावसाकड़े, अरुण कांबले, वनिता नागतोडे,

ज्योति भैंसारे, आशा तुलावी, जयंत पाटील हरडे, गुटनेता तथा पार्षद विकास प्रधान, गिरधर तितराम, पूर्व जपि सदस्य प्रभाकर तुलावी, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष इलियास पठाण, पूर्व नगराध्यक्ष श्याम उईके समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, किसान, खेतिहर मजदूर तथा बेरोजगार युवक शामिल हुए थे.

जनगणना में ओबीसी के लिए स्वतंत्र कॉलम ओबीसी समाज की अलग से बनाकर जनगणना कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई.

प्रारूप मतदाता सूची होगी जारी

संवाददाता । वर्धा जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष महन पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो गई है. सोमवार, 31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. प्रारूप सूची पर नागरिक 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इन पर सुनवाई एवं निर्णय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के प्रस्ताव को भारत

निर्वाचन आयोग ने 24 अगस्त को मंजूरी दी है. प्रारूप मतदाता सूची संबंधित विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी. साथ ही विधानसभा क्षेत्रवार आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची प्रकाशित की जाएगी. प्रारूप सूची जारी होने के बाद 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक अनमैच एवं विसंगति वाले मतदाताओं तथा दावे-आपत्तियों दर्ज कराने वाले मतदाताओं को संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय से नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके बाद सुनवाई लेकर दावे और आपत्तियों पर निर्णय किया

जाएगा. यदि किसी नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा गलती से नाम हट गया है, तो उसे 30 सितंबर तक पुनः नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है. इसके लिए निर्धारित फॉर्म नंबर 6 भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक भी इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच फॉर्म नंबर 6 के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.

गड़चिरोली शहर की स्थिति, उपाययोजना की हो रही मांग

तेज रफ्तार वाहनों के चलते दुर्घटना होने की संभावना

सड़कों से दौड़ती तेज रफ्तार वाहनों के चलते दुर्घटना होने की गंभीर संभावना भी जताई जा रही है. गड़चिरोली जिला मुख्यालय में अनेक राष्ट्रियकृत बैंक शाखाएं हैं. लेकिन पिछले अनेक वर्षों से इन बैंक शाखाओं के सामने पार्किंग की सुविधा नहीं है. जिसके कारण बैंक में आनेवाले ग्राहकों को वाहन रखने संदर्भ में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बैंक ग्राहकों को होनेवाली परेशानियों की ओर गंभीरता से ध्यान देकर तत्काल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. ऐसी बात कही जा रही है.

ग्राहकों को अपनी वाहन सड़क किनारे रखनी पड़ रही है. ऐसे में शहर के चारों मुख्य मार्गों पर यातायात कर्मी तैनात रहते हैं. जिससे सड़कों पर वाहन होने पर कार्रवाई की जाती है. जिसके कारण बैंकों में पहुंचाने वाले

वाहनधारक ग्राहकों को अनेक बार पुलिस कार्रवाई का भय लगा रहा है. शहर के चंद्रपुर मार्ग राष्ट्रीयकृत बैंकों की तीन प्रमुख शाखाएं होकर सर्वाधिक बैंक ग्राहक इन्हीं बैंक शाखाओं में हैं. वहीं प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या

बैंक ग्राहक संबंधित बैंक शाखाओं में बैंकींग व्यवहार करने के लिये आ रहे हैं. लेकिन बैंक शाखाओं के सामने पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण बैंक के ग्राहकों को मजबूरी में अपनी वाहन सड़क किनारे रखनी पड़ रही है.

एसडीएम कार्यालय पर महामोर्चा

बैलगाड़ियों के साथ दी दस्तक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीपीओ को सौंपा ज्ञापन

में आम जनता और गरीब वर्ग की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के मांग की गई. मोर्चे में देसाईगंज पंस के पूर्व सभापति परसराम टिकले, कांग्रेस के कुरखेड़ा तहसील अध्यक्ष जीवन पाटील नाट, देसाईगंज के तहसील अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, आरमोरी के तहसील अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, कोरची के तहसील अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, पूर्व उपसभापति नितीन राऊत, श्रीराम दुग्गा, प्रशांत कोराम, वामनराव सावसाकड़े, अरुण कांबले, वनिता नागतोडे,

ज्योति भैंसारे, आशा तुलावी, जयंत पाटील हरडे, गुटनेता तथा पार्षद विकास प्रधान, गिरधर तितराम, पूर्व जपि सदस्य प्रभाकर तुलावी, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष इलियास पठाण, पूर्व नगराध्यक्ष श्याम उईके समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, किसान, खेतिहर मजदूर तथा बेरोजगार युवक शामिल हुए थे.

जनगणना में ओबीसी के लिए स्वतंत्र कॉलम ओबीसी समाज की अलग से बनाकर जनगणना कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई.

पर्व शांतिपूर्ण मनाने मंडलों का सहयोग जरूरी



वर्धा : आगामी दिनों में जिले में विभिन्न त्योहार और उत्सव मनाए जाएंगे. सभी त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों, इसके लिए उत्सव मंडलों और नागरिकों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील जिलाधिकारी वान्मथी सी ने की.

जिलाधिकारी कार्यालय में आगामी त्योहारों के महेनजर शांति एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, प्रभारी निवासी उपजिलाधिकारी प्रताप वाघमारे, परिवीक्षाधीन अधिकारी शोभिता पाठक सहित शांति नागरिकों के सदस्य एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. जिलाधिकारी ने गणेशोत्सव के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए. विसर्जन मार्ग से

अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुगम करने, आवश्यक स्थानों पर सड़कों की मरम्मत तथा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए. साथ ही आवारा पशुओं और कुत्तों से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए भी आवश्यक उपाय करने को कहा गया. उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान डीजे की आवाज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए. मंडलों द्वारा लेजर लाइट का उपयोग नहीं किया जाए तथा रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल न किया जाए. डीजे की ध्वनि के संबंध में पुलिस विभाग से प्रमाणपत्र लेना आवश्यक रहेगा. नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल ने भी नागरिकों और मंडलों से त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने तथा अपनी किसी भी गतिविधि से उत्सव के माहौल को प्रभावित नहीं करने की अपील की.

गोंदिया जिले की एसआईआर प्रारूप मतदाता सूची जारी

१ लाख ६० हजार ६४६ मतदाताओं के कटे नाम



संवाददाता / गोंदिया
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार चलाए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत 17 अगस्त तक शत-प्रतिशत डिजिटायजेशन का काम पूर्ण किया गया है। जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। जिले में कुल 11 लाख 23 हजार 805 मतदाताओं की संख्या दर्ज थी।

जिसमें 1 लाख 60 हजार 646 मतदाताओं के वोट प्रारूप मतदाता सूची में कम हो गए हैं। जिले में प्रारूप मतदाता सूची में पुरानी मतदाता सूची से 1 लाख 60 हजार 646 मतदाता कम हुए हैं। इनमें से 49 हजार 170 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 15 हजार 309 मतदाता अभियान के दौरान घर में अनुपस्थित पाए गए। 78 हजार 951 मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं। 17 हजार 216 मतदाताओं ने अपने नाम

सबसे अधिक गोदिया विधानसभा क्षेत्र में कटे नाम

प्रारूप मतदाता सूची में जिले में कुल 9 लाख 63 हजार 159 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। जिले में चार विधानसभा क्षेत्र का समावेश है। इनमें सबसे अधिक मतदाताओं के नाम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में कटे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 68 हजार 237 वोट मतदाता प्रारूप सूची में दर्ज है, जो पहले की मतदाता सूची का 82.29 प्रतिशत है। अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 29 हजार 882 मतदाता प्रारूप सूची में शामिल हैं। जिसका प्रतिशत 88.71 है। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 22 हजार 553 मतदाता प्रारूप सूची में दर्ज किए गए हैं। जिसका प्रतिशत 83.08 है। इसी प्रकार आमगांव विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 42 हजार 487 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं। जिसका प्रतिशत 89.54 है। इस प्रकार कुल 11 लाख 23 हजार 805 मतदाताओं में से 1 लाख 60 हजार 646 मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण संशोधन में कम हो गए हैं। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मंदार पत्की ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत घर-घर जाकर मतदाता सूची जांचने के दौरान कुल 1 लाख 60 हजार 646 मतदाता कम हुए हैं। जिनमें मृत मतदाताओं के साथ ही स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए मतदाताओं एवं एसआईआर के दौरान घरों में अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं का भी समावेश है।

नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दूसरे जिलों अथवा गांवों में पंजीकृत कराए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपील की गई है कि प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता अपना

नाम जांच कर लें एवं जिनके नाम इस सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपील करें। जिलाधिकारी और जिला

निर्वाचन अधिकारी मंदार पत्की ने नागरिकों से प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और 30 सितंबर तक आवश्यक दावे और आपतियां प्रस्तुत करने की अपील की है।

भारतीय बौद्ध महासभा की सालेकसा तालुका शाखा का गठन



संवाददाता / डोंगरगांव
दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया-भारतीय बौद्ध महासभा गोंदिया जिला शाखा की ओर से २६ अगस्त २०२६, बुधवार को नागार्जुन बौद्ध विहार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सालेकसा में सालेकसा तालुका शाखा का गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा गोंदिया जिलाध्यक्ष नरेश मेश्राम ने की। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव अनिल मौर्य ने किया। इस अवसर पर तालुका अध्यक्ष पद के लिए निर्दोष साखरे के नाम की घोषणा राजेंद्र बडोले सर ने की। उनके नाम का अनुमोदन कामेश साखरे ने किया। उपस्थित

निर्दोष साखरे बने तालुका अध्यक्ष

समाजबंधुओं की सहमति से निर्दोष साखरे को सालेकसा तालुका अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष निर्दोष साखरे का उपस्थित पदाधिकारियों एवं समाजबंधुओं ने अभिनंदन कर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान संगठन को तालुका स्तर पर मजबूत करने, समाज में एकता एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ाने तथा महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जया सुखदेव, ललकार बंसोड़, शिवदास साखरे, संतोष राजूत, निशा जनबंधु, कुंती नंदेश्वर, राजेंद्र बडोले, कामेश

साखरे, सुभाष लालचंद साखरे, कुसोबा बडोले, विशाल रमेश कोटांगले, सागर बोरकर, कुवरलाल राजूत, आशीष टेंभुर्ण, अनिल तीरपुडे, रमेश अंबादे, प्रवीण कोटांगले, सिद्धार्थ साखरे, बी.एस. भास्कर सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। तालुका शाखा के गठन से सालेकसा क्षेत्र में भारतीय बौद्ध महासभा के सामाजिक एवं संगठनात्मक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद व्यक्त की गई। कार्यक्रम का संचालन अनिल मौर्य ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन अनिल तीरपुडे ने किया।

स्वास्थ्य केंद्र का फिलहाल स्थानांतरण नहीं

अंतिम निर्णय होने तक स्वास्थ्य समिति से नहीं मिलेगी मंजूरी : सुरेश हर्षे

संवाददाता / आमगांव
तहसील अंतर्गत घाटटेमनी जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, गोंदिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष व स्वास्थ्य विभाग के सभापति सुरेश हर्षे ने स्पष्ट किया है कि बनागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जब तक यह तय नहीं हो जाता कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत किन गांवों को जोड़ा अथवा हटाया जाना है, तब तक जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्थानांतरण को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सालेकसा मार्ग स्थित शुभमंगल



कार्यालय के सभागृह में आयोजित चर्चा के दौरान हर्षे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार जिन क्षेत्रों में ग्रामीण अस्पताल उपलब्ध हैं, वहां से लगभग 6

किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इसी आदेश के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ

क्षेत्र के विधायक करें प्रयास

आमगांव ग्रामीण अस्पताल, कामठा चौक स्थित 'आपला दवाखाना' तथा सालेकसा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनागांव को किकरीपार स्थानांतरित करने का विचार सामने आया था। सुरेश हर्षे ने कहा कि बनागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थानांतरण रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित 6 किलोमीटर की दूरी संबंधी शर्त हटाने के लिए क्षेत्रीय विधायक को शासन स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए उनका पूरा समर्थन रहेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस

संबंध में जिला की स्थायी समिति के अध्यक्ष लायकसाम भेंडारकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्ताव

ध्वनिमत से पारित किया गया था। हर्षे ने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग इस मामले में उनका नाम लेकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनागांव की रोगी कल्याण समिति की फरवरी-मार्च 2026 में हुई बैठक में केंद्र के स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने की चर्चा है। बैठक की अध्यक्षता जिला सदस्य व रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष किशोर महारवाड़े ने की थी।

मुख्य सड़क पर व्यापारियों का कब्जा, ट्रैफिक जाम हुआ आम

दुकानों के बाहर रखे सामान और वाहनों की पार्किंग से सड़कें हुई संकरी

संवाददाता / अर्जुनी मोर
शहर की मुख्य सड़क पर दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दुकानों के बाहर सामान, ठेले और वाहन खड़े किए जाने से सड़क की चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है। इस कारण राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार, मुख्य सड़क के दोनों ओर कई व्यापारियों ने दुकानों की निर्धारित सीमा से बाहर तक सामान फैला रखा है। कई स्थानों पर ग्राहक अपने वाहन भी



सड़क किनारे खड़े कर देते हैं। इससे सड़क पर वाहनों के आवागमन के लिए जगह कम पड़ जाती है और व्यस्त समय में जाम की स्थिति आम हो गई है। फुटपाथ और सड़क किनारे का हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित होने के बावजूद अतिक्रमण और व्यापारिक गतिविधियों के कारण

राहगीरों को मजबूरी में मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच पैदल चलने से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। नागरिकों ने प्रशासन और नगर निकाय से मुख्य सड़क का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने तथा यातायात व्यवस्था सुचारु करने की मांग की है।

ग्राम पंचायत अधिकारियों के बहिष्कार के बीच रोजगार सेवक ने ली ग्रामसभा

तंटामुक्त समिति अध्यक्ष का भी हुआ निर्विरोध चुनाव

संवाददाता / डोंगरगांव
स्थानीय डोंगरगांव ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारियों के बहिष्कार के चलते २५ अगस्त को आयोजित ग्रामसभा रोजगार सेवक द्वारा लिए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरपंच सौ. कोमेश्वरीताई नरेंद्र टेंभरे की अध्यक्षता में ग्रामसभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम रोजगार सेवक गोविंद पटले ने ग्रामसभा की कार्यवाही संचालित की। ग्रामसभा की शुरुआत में ग्राम पंचायत सदस्य सोनुभाऊ कटरे द्वारा घरकुल लाभार्थियों की सूची का वाचन किया गया। सूची में कुल ३७५ लाभार्थियों के नाम शामिल होने की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष लाभार्थियों के नाम पढ़कर सुनाए गए। इसके पश्चात महात्मा गांधी तंटामुक्त समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया। ग्रामसभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति से दयारामजी तुमसरे सर का निर्विरोध चयन



किया गया। ग्रामसभा में उपसरपंच सुरेश ठाकरे, ग्राम पंचायत सदस्य अनिल गौतम, शैलेश राजूत, मनोहर कटरे, सौ. जयमालाताई गौतम, काजल बंसोड़, वैशाली टेंभरे, शालु बावने, वर्षा राजूत, गणेश उके (पानी वाटप), बोदल बावने (इलेक्ट्रिकल), सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष तथा माजी सरपंच नरेंद्र पुरनलालजी टेंभरे, पोस्टमास्टर खुमनशींग पटले, माजी तंटामुक्त

समिति अध्यक्ष ऋषीपाल तुरकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामसभा में लगभग २५५ महिला-पुरुषों की उपस्थिति रही। इस दौरान ३७५ घरकुल लाभार्थियों के नाम मनोहर कटरे द्वारा उपस्थित नागरिकों को पढ़कर सुनाए गए। ग्राम पंचायत अधिकारियों की अनुपस्थिति के बावजूद ग्रामसभा आयोजित किए जाने को लेकर ग्रामीणों में चर्चा रही।

जाहिरसुचना

श्री.अशोक शुक्ल राजूत इनके नाम से नगर परिषद रिकार्ड में नाम दर्ज है. जिसका वार्ड क्रमांक – 7 वार्ड का नाम – गोविंदपूर छोटा गोंदिया वार्ड है. मालमत्ता क्रमांक – 7/5 14 है. उक्त मालमत्ता धारक का निधन दिनांक :- 30/12/2002 को हो चुका है. इनके निधन उपरांत इनके वारस 1) श्री.प्रदिप अशोक राजूत इन्होंने वारसान आधार पर हस्तांतरण हेतु आवेदन सादर किया है. हस्तांतरण पर आक्षेप हो तो यह सुचना प्रकाशित होने के पश्चात 15 दिन के भितर अपना आक्षेप इस कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेज सहित सादर करेंगे. आक्षेप प्राप्त न होने पर हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी.

मुख्य अधिकारी
नगर परिषद गोंदिया

जाहिरसुचना

श्री.स्व.दिलीप परसराम उके इनके नाम से नगर परिषद रिकार्ड में नाम दर्ज है. जिसका वार्ड क्रमांक – 34 वार्ड का नाम – सेठ सुरजमुल वार्ड है. मालमत्ता क्रमांक – 34/64 है. उक्त मालमत्ता धारक का निधन दिनांक :- 08/10/2020 को हो चुका है. इनके निधन उपरांत इनके वारस 1) श्री.कार्तिक दिलीप उके, 2) श्रीमती सुनिताबाई दिलीप उके इन्होंने वारसान आधार पर हस्तांतरण हेतु आवेदन सादर किया है. हस्तांतरण पर आक्षेप हो तो यह सुचना प्रकाशित होने के पश्चात 15 दिन के भितर अपना आक्षेप इस कार्यालय में प्रमाणित दस्तावेज सहित सादर करेंगे. आक्षेप प्राप्त न होने पर हस्तांतरण की कार्यवाही की जायेगी.

मुख्य अधिकारी
नगर परिषद गोंदिया